Successful Implementations of SPARROW in MADHYA PRADESH

For the state of Madhya Pradesh, **SPARROW** application was deployed at the State Data Centre in the year 2017. After successful rollouts for officers of State Administrative Service (SAS) and State Police Service (SPS), Government of Madhya Pradesh mandated for its adoption across all the govt. departments of the state.

Accordingly, this G2E software solution has been replicated across 10 departments in MP till now. It has resulting in reduced delays, enhanced transparency and timely conduction of DPCs. Filing of Annual Immovable Property Returns (IPRs) of employees and their public disclosure on respective departmental websites has also been facilitated through this application.

The Implementations so far are listed below :

S.No	Department/HOD	Name of Service/Cadre	No of users
1	GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT	MP-State Administrative Service	687
2	MP-POLICE HEAD QUARTER (PHQ)	MP-State Police Service	1097
	HOMEGUARD, CIVIL DEFENCE & DISASTER MANAGEMENT	MP-State Homeguard Service (Class-1)	15
		MP-State Homeguard Service (Class-2 & 3)	46
	PUBLIC PROSECUTION	MP-State Public Prosecution Service (Class-1 & 2)	851
3	PRINCIPAL REVENUE COMMISSIONER	MP-Junior Administrative Service (PRC)	1016
	COMMISSIONER LAND RECORD	MP-CLR Executive Service (REVENUE INSPECTOR)	1580
		MP-Junior Administrative Service (CLR)	151
		MP-CLR-Technical Service	317
4	DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES	MP-State Medical Services (gazetted)	4030
5	COMMISSIONER COMMERCIAL TAX	MP-State Taxation Service (Class-1)	72
		MP-State Taxation Service (Class-2 & 3)	906
	EXCISE COMMISSIONER	MP-State Excise Service (Class-1)	24
		MP-State Excise Services (Class-2 & 3)	231
	INSPECTOR GENERAL REGISTRATION AND SUPERINTENDENT OF STAMPS	MP-State Registration Service(Class-1)	7
		MP-State Registration Service(Class-2 & 3)	39
6	MANTRALAYA	MP-Mantralaya Service (Class-1 & 2)	153
		MP-Mantralaya Service (Class- 3)	1071
7	FINANCE DEPARTMENT	MP-STATE FINANCE SERVICE (Class-1&2)	520
	DIRECTORATE TREASURY AND ACCOUNTS	MP-DTA-Treasury IT Service	200
		MP-DTA-Subordinate Account Service	200
		MP-DTA-Treasury Clerical Service	300
8	DIRECTORATE FOREST	MP- State Forest Service	63
9	DIRECTORATE OF MINING	MP -State Mining Service (Class-1)	11
10	REGISTRAR COOPERATIVE SOCIETIES	MP- State Cooperative Service (Class 1)	16
		TOTAL USERS	**13,603**

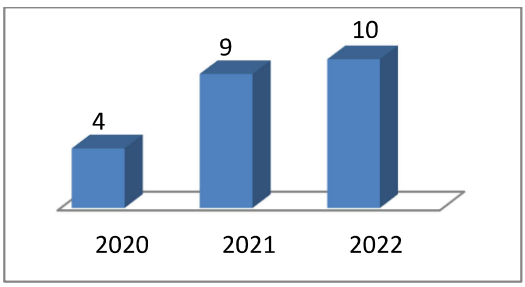

SPARROW rollout at State Secretariat received good media coverage lately. Excerpts placed below :-

दैनिक भास्कर

डीबी स्टार भोपाल 08-08-2022

आज बात कर्मचारियों की, क्योंकि भोपाल को कर्मचारियों का शहर भी कहा जाता है

CR दिखाने और आपत्ति दर्ज कराने का निर्णय अधिकारी-कर्मचारियों के बीच टकराव कम करने के साथ ही प्रमोशन के अवसर भी बढ़ाएगा

भोपाल | DBStar

प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को उनकी सीआर दिखाने और आपत्ति दर्ज कराने का मौका देने का निर्णय लिया है। पहले अफसर सीआर तय करते थे। कर्मचारियों को प्रमोशन और अन्य सुविधाओं से वंचित हो जाते थे या फिर उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन यदि अब उन्हें लगता है तो वे आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे। इस संबंध में डीबी स्टार ने कर्मचारी नेताओं से उनकी राय जानी तो सभी ने निर्णय को अच्छा बताया और कहा कि आदेश का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से होना चाहिए।

DBStar परिचर्चा

अजय श्रीवास्तव, प्रांताध्यक्ष, निगम-मंडल अधिकारी-कर्मचारी, महासंघ

सीआर कर्मचारी को दिखाने, आपत्ति दर्ज कराने का मौका और संशोधन करने का निर्णय अच्छा है। कर्मचारी 365 दिन काम करते हैं, लेकिन एक दिन की मामूली चूक से पूरे सालभर की मेहनत खराब हो जाती थी। इससे सीआर प्रभावित होती थी। अब कर्मचारियों और अफसरों के बीच भी बेहतर तालमेल रहेगा और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। आपत्ति के बाद संशोधन भी किया जा सकेगा।

उमाशंकर तिवारी, प्रदेश सचिव, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ

प्रदेश सरकार का आदेश कर्मचारियों के हित में अच्छा है। इसका क्रियान्वयन ठीक ढंग से होना चाहिए। कर्मचारी अपनी सीआर देख सकेंगे, बल्कि संतुष्ट न होने की दशा में आपत्ति भी दर्ज करा सकेंगे। आपत्ति सही पाए जाने पर सीआर को सुधार के बाद प्रमोशन का मौका मिलेगा। कई बार अफसर दुर्भावनावश कर्मचारियों के विपरीत लिख देते थे। अब उसमें संशोधन भी हो सकेगा।

अरुण भार्गव, अध्यक्ष, नगरीय प्रशासन विभागीय समिति

सीआर दिखाने का निर्णय अच्छा है। पहले तो सीआर लाना ही मुश्किल होता था। अक्सर अफसर अपना दायित्व नहीं समझते थे। विचारों में मतभेद के कारण दिक्कतें आती थीं। अफसरों के तबादले हो जाते थे तो दिक्कतें आती थीं। अब कर्मचारी आपत्ति भी दर्ज करवा सकेंगे और संशोधन भी सीआर में हो सकेगा। सरकार को इस निर्णय का क्रियान्वयन अच्छी तरह से करना चाहिए।

मोहन अय्यर, जिला अध्यक्ष, मप्र तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन

पहले तो सीआर देखने को नहीं मिलती थी। बहुत मुश्किल हो जाता था। कर्मचारी भी अपनी सीआर को लेकर चिंतित रहते थे। अब पता चल सकेगा कि ठीक है या नहीं। कर्मचारियों और अफसरों के बीच संबंधों में भी किसी तरह की कड़वाहट नहीं होगी। आपत्ति के बाद उसमें संशोधन हो सकेगा। यह अच्छा निर्णय है। इससे कर्मचारियों को लाभ होगा। उनकी चिंताएं भी दूर हो सकेंगी।

दैनिक भास्कर

भोपाल 05-08-2022

ऑनलाइन देख सकेंगे सीआर

सीआर अब सीक्रेट नहीं, कर्मी ओके करेंगे, तभी फाइनल होगी

भोपाल अब सीआर यानी गोपनीय चरित्रावली सीक्रेट नहीं ओपन होगी, जिसे कर्मचारी देख सकेंगे। अभी तक नकारात्मक सीआर होने की स्थिति में ही कर्मचारी को बताई जाती थी। नई व्यवस्था के अनुसार सीआर ऑनलाइन रहेगी। तृतीय श्रेणी संवर्ग के पदों की सीआर सेक्शन आफिसर के द्वारा लिखी जाएगी। इसका परीक्षण अंडर सेक्रेटरी और स्वीकृत डिप्टी सेक्रेटरी करेगा। इसके बाद सीआर उत्कृष्ट, औसत या खराब होने की स्थिति में कर्मचारी के पास भेजी जाएगी। कर्मचारी ओके करेगा तभी फाइनल मानी जाएगी। यदि सीआर खराब है और कर्मचारी आपत्ति दर्ज करता है तो उसे दोबारा सेक्शन आफिसर के पास भेजा जाएगा अभी तक प्रमोशन में सीनियरिटी देखी जाती थी, लेकिन नए पदोन्नति नियम में मेरिट कम सीनियरिटी ही तरक्की का पैमाना होगा। प्रत्येक कर्मचारी की पदोन्नति में पांच साल की सीआर देखी जाएगी।

- Compiled by Sucheeta Kak, Scientist 'F' NICMPSC